भारत ने वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा

लंदन(आरएनएस)। लंदन में खेले जा रहे वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफ़ाइनल टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया. लंदन में ओवल पर भारतीय क्रिकेट टीम बेशक पाकिस्तान के दबाव में दिखी लेकिन लंदन में ही ओवल से क़रीब आधे घंटे की दूरी पर ली-वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर पर नज़ारा बिल्कुल उल्टा था. हॉकी मैदान पर भारतीय हॉकी टीम पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी रही. मैच के पहले क्वार्टर के ख़त्म होने से पहले 13वें मिनट में ही जूनियर वर्ल्ड कप के हीरो हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर टीम इंडिया को बढ़त दिलाई. 21वें मिनट में भारतीय फ़ॉरवर्ड ने शानदार सेट पीस तैयार किया और तलविन्दर सिंह ने दूसरा गोल कर टीम की बढ़त बड़ी कर दी. 24वें मिनट में तलविन्दर सिंह ने एक और गोल किया और हाफ़ टाइम तक भारत 3-0 की बढ़त के साथ पाक पर हावी दिखा. दूसरे हाफ़ में ये सिलसिला जारी रहा. 33 वें मिनट में हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर से एक और गोल बनाया. स्कोरबोर्ड पर भारत 4-0 से आगे हो गया. थर्ड क्वार्टर के ख़त्म होने तक ये स्कोर बरक़रार रहा. आख़िरी क्वार्टर (47 वें मिनट में) भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल दिखाया और पाक डिफेंस को भेद दिया. पांचवां गोल आकाशदीप के स्टिक के ज़रिये आया. दो मिनट बाद ही प्रदीप मोर ने एक और गोल किया और भारत को आधा दर्जन गोलों की बढ़त मिल गई. मैच ख़त्म होने से तीन मिनट पहले राइट विंग से मिले क्रॉस मो. उमर भुट्टा ने गोल कर स्कोर के अंतर को 6-1 कर दिया. लेकिन अगले ही मिनट में आकाशदीप ने इसका बदला ले लिया. टूर्नामेंट में भारत ने इससे पहले स्कॉटलैंड (4-1) और कनाडा (3-0) को हराया. जबकि पाकिस्तान को हॉलैंड (0-4) और कनाडा के हाथों (0-6) हार का सामना करना पड़ा. भारत की टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी जीत और पाकिस्तान की तीसरी हार है. लीग के आख़िरी मैच में भारत की टक्कर 20 जून को हॉलैंड से होगी.

इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज़ चैंपियन बने श्रीकांत, जापान के काजुमासा सकाई को हराया

नई दिल्ली(आरएनएस)। गुंटूर के 24 साल के किदाम्बि श्रीकांत ने जापान के काजुमासा सकाई को 21-11, 21-19 से फ़ाइनल में हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज़ का ख़िताब अपने नाम कर लिया. इसी टूर्नामेंट के सेमीफ़ाइनल में श्रीकांत ने दक्षिण कोरिया के वर्ल्ड नंबर एक सोन वैन को शिकस्त देकर सबको अपना कायल कर दिया था. फ़ाइनल मैच जीतने में श्रीकांत ने सिर्फ़ 37 मिनट का वक्त लिया. ओवल पर भारत और पाकिस्तान के फ़ाइनल क्रिकेट मैच शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद इंडोनेशिया के जकार्ता कनवेंशन सेंटर पर एक और रोमांचक फ़ाइनल शुरू हो गया. 2014 में चाइना ओपन के फ़ाइनल में चीन के लिन डैन जैसे दिग्गज को हराने वाले श्रीकांत आंध्रप्रदेश में गुंटूर के किदाम्बि श्रीकांत की टक्कर जापान के वर्ल्ड नंबर 47 वरीयता प्राप्त काजुमासा सकाई से थी, जिन्होंने भारत के एच एस प्रणॉय को सेमीफ़ाइनल में शिकस्त दी थी. हैदराबाद के रहने वाले श्रीकांत और जापान के काजुमासा सकाई के बीच ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था इसलिए शुरुआत से ही दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे को अच्छी तरह आंकने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन धीरे-धीरे 22वीं वर्ल्ड रैंकिंग वाले श्रीकांत ने सकाई के ख़िलाफ़ पहले गेम में 13-8 और फिर 19-9 की बढ़त कायम कर ली. श्रीकांत ने पहला गेम सिर्फ़ 13 मिनट में 21-11 से अपने पक्ष में कर लिया. दूसरे गेम की शुरुआत में श्रीकांत ने थोड़ा खुलकर खेलने की कोशिश की लेकिन कुछ ग़लतियों और कुछ ग़लत जजमेंट की वजह से 4-9 से पिछड़ते दिखे. ज़बरदस्त वापसी करते हुए श्रीकांत स्कोर को 15-15 और फिर 19-19 की बराबरी पर ले आए. लेकिन आख़िर कार श्रीकांत ने 21-11 से दूसरा गेम भी अपने नाम कर लिया. 213 सिंगल्स मैचों में श्रीकांत की ये 138 वीं जीत (75 में हार) है. श्रीकांत का ये तीसरा सुपर सीरीज़ ख़िताब है. श्रीकांत की बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग 3 रह चुकी है. फ़िलहाल उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 22 है. लेकिन इस जीत से उन्हें रैंकिंग का फ़ायदा भी ज़रूर होगा।

अब अगले साल नहीं होगा टी20 वर्ल्ड कप

लंदन(आरएनएस)। विश्व ट्वेंटी20 चैम्पियनशिप के 7वें टूर्नामेंट को रद्द करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और इस 2020 में आयोजित किया जा सकता है क्योंकि 2018 में अधिकांश टॉप सदस्य देश द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं में व्यस्त हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के शीर्ष पदस्थ सूत्रों के अनुसार आईसीसी विश्व टी20 के अगले टूर्नामेंट का आयोजन 2020 में ही होगा लेकिन अभी इसके लिए स्थल तय नहीं किया गया है. इस संदर्भ में आईसीसी के एक प्रभावशाली सूत्र ने कहा, हां, यह सही है कि हम 2018 में विश्व टी20 टूर्नामेंट को आयोजित नहीं कर रहे. किसी स्थल पर फैसला नहीं किया गया है. मुख्य कारण यह है कि सदस्य देशों के बीच काफी द्विपक्षीय सीरीज होनी हैं. 2018 में टूर्नामेंट का कार्यक्रम तय करने की संभावना नहीं है. हालांकि पूरी संभावना है कि 2020 में इस टूर्नामेंट की वापसी होगी.

2020 में टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की होगी वापसी : सूत्र ने कहा, हां, 2020 में टूर्नामेंट की वापसी होगी. यह दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है. द्विपक्षीय सीरीज के अलावा अन्य कारण यह है कि काफी आईसीसी टूर्नामेंट होने के कारण सदस्य देशों का मानना है कि उन्हें भी समय की जरूरत है. अब तक दक्षिण अफ्रीका (2007), इंग्लैंड (2009), वेस्टइंडीज (2010), श्रीलंका (2012), बांग्लादेश (2014) और भारत (2016) में विश्व टी20 टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है.

द्विपक्षीय सीरीज से देशों की होती है कमाई : द्विपक्षीय सीरीज से सभी देशों को कमाई होती है जिसका बड़ा हिस्सा प्रसारण करार से आता है. विशेषकर जब भारत किसी देश का दौरा करता है तो मेजबान बोर्ड टीवी प्रसारण अधिकार से लाखों डॉलर की कमाई करता है. यह पूछने पर कि क्या विश्व टी20 का आयोजन नहीं होना आईसीसी के लिए झटका होगा, सूत्र ने कहा, बिलकुल भी नहीं. पर्याप्त टी20 लीग मौजूद हैं और प्रशंसकों के लिए काफी क्रिकेट मौजूद है. भारतीय टीम अगले साल अधिकांश समय दौरे पर रहेगी जिसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से होगी जिसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी जाना है.

हो सकती है विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप : फिलहाल 2021 में चैम्पियंस ट्रॉफी के अगले टूर्नामेंट के भारत में आयोजन का कार्यक्रम है. कल से यहां शुरू हो रहे आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप पर चर्चा हो सकती है. आईसीसी लंबे समय से सभी प्रारूपों में कम से कम एक विश्व प्रतियोगिता शुरू करने की योजना बना रहा है. पता चला है कि बीसीसीआई अब प्रस्तावित अपने 39 करोड़ डॉलर के हिस्से में इजाफे का आग्रह कर सकता है लेकिन सदस्य देश इसे अनुचित समझते हैं तो उनके इस मांग को मानने की संभावना नहीं है.

सीआईसी ने पीएमओ से पूछा, ब्रिटिश काल के लोगो का इस्तेमाल क्यों करती है टीम इंडिया

नई दिल्ली(आरएनएस)। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अलावा खेल और विधि मंत्रालयों से पूछा है कि भारतीय क्रिकेट टीम अब भी बीसीसीआई के उस लोगो का इस्तेमाल क्यों कर रही है जो स्टार आफ इंडिया सम्मान की तरह दिखता है जिसे औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश अपने पसंदीदा राजाओं को दिया करते थे. आयोग ने कहा है कि बीसीसीआई का चिह्न ब्रिटिश राज के स्टार ऑफ आर्डर की तरह है. सीआई ने पूछा, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संघर्ष के बाद भारत के ऊपर अपने आधिपत्य को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने वफादार भारतीय राजाओं को सम्मानित करने के लिए नाइटहुड का नया आर्डर शुरू किया. 1948 के बाद ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया गया. क्या किसी ने गौर किया कि बीसीसीआई अब भी इस औपनिवेशिक विरासत से जुड़ा हुआ है. हमारी टीम अब भी इस लोगो के साथ खेलती है. सीआईसी ने सरकार से पूछा है कि वे इस लोगो को सच्चे भारतीय प्रतीक जैसे तिरंगा या चार शेर या अशोक के धर्म चक्र या किसी अन्य जिसका फैसला वह स्वयं करे, उससे क्यों नहीं बदल देती.आयोग ने कड़े फैसले में साथ ही सरकार से जानना चाहा है कि वे स्पष्ट करे कि लोक सभा में जवाब देने बावजूद सरकार बीसीसीआई को आरटीआई कानून के दायरे में क्यों नहीं ला रही. सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर यह सवाल पूछा है. उन्होंने साथ की सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खेलों में धोखाधड़ी और मैच फिक्सिंग रोकने के लिए विधेयक की स्थिति का खुलासा करें. सूचना आयुक्त ने साथ ही खुलासा करने को कहा है कि सरकार अंतर र्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक समान नीति क्यों नहीं लाती जिससे कि विभिन्न राज्य सरकारों के बीच प्रचार हासिल करने की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके.

गांगुली ने सहवाग से कहा अभी आपको मेरे सामने इंटरव्यू देना है

नई दिल्ली(आरएनएस)। इंग्लैंड में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के एक मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली की जोड़ी देखने को मिली. इस दौरान दोनों जमकर मस्ती करते हुए नजर आए. दोनों के बीच मजाक-मजाक में जुबानी जंग भी देखने को मिली. **गांगुली ने दिया सहवाग को जवाब :** इस दौरान एक मौके पर गांगुली ने सहवाग को चेतावनी तक दे डाली. साथ ही दोनों के बीच दौड़ का चैलेंज भी लग गया. हालांकि, ये चेतावनी और चैलेंज दोनों ने हंसी मजाक में किया. कमेंट्री में सहवाग ने गांगुली के रनिंग बिटविन विकेट पर सवाल उठाए. सहवाग का कहना था कि दादा अपने जमाने में तेजी से रन नहीं ले पाते थे. इसके कराण वे रन आउट होते थे और टीम का स्कोर भी प्रभावित होता था. इसके बाद गांगुली भी अटैकिंग मूड में आ गए. उन्होंने तुरंत सहवाग की बातों का काउंटर किया. कुछ देर बाद गांगुली हाथ में एक पर्ची लिए नजर आ रहे थे. उस पर्ची पर आंकड़े थे. गांगुली ने कहा- मैंने आंकड़े निकलवाए हैं. सहवाग आपको पता है- मेरा रन बिटविन विकेट 36 प्रतिशत था जबकि आपका 24 प्रतिशत. **गांगुली ने ली सहवाग की चुटकी :** इसी दौरान गांगुली ने चुटकी लेते हुए सहवाग से कहा- अभी आपको मेरे सामने इंटरव्यू देना है, इसलिए आप सही से रहें और सच्ची बात बोलें. बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया के लिए नया कोच चुना जाना है. इसके लिए 6 बड़े नाम आवेदन के तौर पर सामने आए हैं. इसमें वीरेंद्र सहवाग का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. बीसीसीआई ने कोच चुनने का जिम्मा सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण को सौंप रखा है. **दोनों के बीच लगा दौड़ का चैलेंज :** इसी दौरान सहवाग और गांगुली के बीच 100 मीटर दौड़ का चैलेंज लग गया.

Business News / बिजनेस न्यूज

जीएसटी परिषद की अगली बैठक 30 जून को

नई दिल्ली(आरएनएस)। जी.एस.टी. काऊंसिल की 17वीं और काफी अहम बैठक खत्म हुई। सरकारी और निजी लॉटरी के लिए जीएसटी होगी अलग-अलग दरें। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 30 जून को होगी। सूत्रों के मुताबिक आज बैठक में 50 से ज्यादा आइटम पर जी.एस.टी. के टैक्स दरों की समीक्षा की जा सकती है। इस दौरान संबंधित सेक्टर की तरफ से आए सुझावों और 5 मुद्दों पर बनाए गए कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। इसके अलावा एंटी प्रॉफिटियरिंग, असेसमेंट एंड ऑडिट और एडवांस रूलिंग पर बनाए गए कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा हो सकती है। सरकार एंटी प्रॉफिटियरिंग के तहत टैक्स में कमी के हिसाब से कीमतें कम करना सुनिश्चित करेगी। ई-वे बिल के नियमों पर भी चर्चा हो सकती है। ई-वे बिल के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लाने ले जाने के नियम शामिल हैं। माना जा रहा है कि आज की बैठक में ई-वे बिल के नियमों को मंजूरी दी जा सकती है।

एसोचौम ने की जीएसटी की तिथि बढ़ाने की मांग

प्रमुख उद्योग संगठन ऐसोचौम ने रिटर्न मॉड्यूल तथा अन्य तकनीकी तैयारियाँ पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की तिथि एक जुलाई से आगे बढ़ाने की माँग की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में एसोचौम ने कहा है कि जीएसटी नेटवर्क (जी एस टी एन) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन कुमार के बयानों से स्पष्ट है कि एक जुलाई से जीएसटी पूरी तरह लागू नहीं हो पाएगा। उसने बताया कि कुमार स्वयं यह कह चुके हैं कि एक माह पहले बीटा टेस्ट के दौरान कुछ खामियों के कारण जीएसटी के रिटर्न फॉर्मेट को पूरी तरह बदल दिया गया है जिसके कारण इसके सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव करने पड़े हैं। नया रिटर्न मॉड्यूल जुलाई के अंत तक तैयार हो पायेगा। यदि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होता है तो पहला रिटर्न अगस्त में भरना होगा। एसोचौम का कहना है कि उस स्थिति में जुलाई के अंत में मॉड्यूल तैयार होने से उसे परखने का समय नहीं मिल पाएगा, साथ ही जिस एक्सेल शीट पर करदाताओं को रोजाना बिक्री के आँकड़े भरने होंगे वह भी 25 जून से ही उपलब्ध होगा। इस तरह करदाताओं के पास इस परखने का भी समय नहीं होगा। उसने कहा है कि जी.एस.टी.एन. की तैयारी की यह स्थिति देखते हुये करदाताओं के लिए जी. एस. टी. को अपनाना मुश्किल होगा।

28 फीसदी कर दायरे वाली वस्तुओं की पुनर्समीक्षा जरूरी

जी.एस.टी. परिषद बैठक से एक दिन पहले छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 प्रतिशत कर दायरे में रखी गई वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है और कहा है कि इसे सिर्फ विलासी वस्तुओं पर ही लगाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली पूर्ण अधिकार प्राप्त जी.एस.टी. परिषद की कल लॉटरी पर कर की दर और ई-वे से संबंधित नियम बनाने और मुनाफा वसूली रोधी कदम तय करने के लिए बैठक करेगी। इस परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। कैट ने एक बयान में माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के तहत 28 प्रतिशत की कर दायरे में रखी गई वस्तुओं के वर्गीकरण पर सवाल उठाया है। उसने जेतली से इन वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कर की यह दर व्यापारियों के बीच व्याकुलता का प्रमुख कारण बन गई है जो पिछले दो दिन से हड़ताल पर हैं और इन वस्तुओं को संबंधित निचली दरों के तहत रखने की मांग कर रहे हैं। कैट का कहना है कि इस कर दर को केवल विलासी वस्तुओं पर लगाया जाना चाहिए।

आईआरसीटीसी के पोर्टल को घुसपैठ से ऐसे बचाएगा रेलवे

नई दिल्ली(आरएनएस)। इन दिनों आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग होने के मामले बढ़ गए हैं। इससे रेल टिकटों की बुकिंग, खासकर तत्काल बुकिंग में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मर्तबा तो पीएनआर स्टेटस तक जानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी रेलवे असमर्थ है। प्राइवेट वेबसाइटों ने रेलवे वेबसाइटों में सेंध लगाकर उनकी हालत पतली कर दी है और सब कुछ जानते हुए भी रेलवे उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में असमर्थ है। सूत्रों के अनुसार रेल यात्रियों को सूचनाएं व सेवाएं देने के नाम पर इन दिनों दर्जनों ऐसी प्राइवेट वेबसाइटें फलफूल रही हैं, जिनका मूल स्रोत आइआरआरसीटी की वेबसाइट है। अपने अनोखे साफ्टवेयर और ऐप के बूते ये रेल ग्राहकों को आइ आर सी टी सी से भी बेहतर व त्वरित सूचनाएं व सेवाएं प्रदान कर रही हैं। लेकिन इनकी ये खूबी आइ आर सी टी सी की वेबसाइट के हैंग होने का कारण बन रही है। आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा, यह जानने के लिए जब हमने रेलवे बोर्ड में आईटी सेल के प्रमुख एडीशनल मेंबर संजय दास से बात की तो उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि क्षमता व कुशलता की दृष्टि से आईआरसीटीसी का पोर्टल विश्व का सबसे बड़ा व सुरक्षित पोर्टल है। लेकिन व्यक्तिगत ग्राहकों के अलावा प्राइवेट वेबसाइटों व टिकटिंग

एजेंटों की अधिकृत व अनधिकृत घुसपैठ के कारण इसे कभी-कभी जाम का शिकार होना पड़ता है। ये साइटें मशीनों व साफ्टवेयर के जरिए एक ही वक्त पर हजारों लोगों की बुकिंग व सूचनाएं एक्सेस करने में सक्षम हैं। हमारी दिक्कत यह है कि एक तो ये वेबसाइटें रेलवे से भी बेहतर और तेज सेवाएं दे रही हैं जिससे लोग इन्हें पसंद करते हैं। जबकि दूसरे, भारत का कोई भी मौजूदा नियम या कानून इन्हें इस कार्य से रोकता नहीं है। यहां तक कि साइबर सुरक्षा कानून में भी इनकी इन गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यही वजह है कि सब कुछ जानने के बावजूद हम इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। हमें यह बखूबी पता है कि कौन सी वेबसाइट क्या कर रही है और उससे हमारी साइट पर कब, कितना लोड बढ़ रहा है। लेकिन कर कुछ नहीं सकते। हम केवल अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं और नई सेवाएं शुरू कर सकते है। वह हम कर भी रहे हैं। हमारी वेबसाइटों पर लोगों को कम से कम परेशानी हो और वे केवल रेलवे की वास्तविक वेबसाइट का ही प्रयोग करें इसके लिए पूर्व में हमने अपने सर्वर की क्षमता को कई गुना बढ़ाया है। जबकि अब हम एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। आगामी 6 जुलाई को लांच होने वाले इस ऐप में प्राइवेट वेबसाइटों द्वारा दी जा रही तकरीबन सभी सेवाएं व सूचनाएं उपलब्ध होंगी।

जहां तक प्राइवेट वेबसाइटों पर नियंत्रण का सवाल है तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति आईआरसीटीसी समेत रेलवे की तमाम वेबसाइटों का व्यावसायिक उपयोग करने के बारे में नियम व शर्तें तैयार करेगी। ताकि निजी साइटों से लाभ की हिस्सेदारी प्राप्त करने के अलावा अपनी वेबसाइटों पर विज्ञापन प्रसारित कर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें। यह समिति यह भी देखेगी कि निजी वेबसाइटों की कौन सी गतिविधियों को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जा ए ताकि वे अपने फायदे के लिए रेलवे का नुकसान न कर सकें। इसके आधार पर साइबर सुरक्षा कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है।

शेयर बाजार में इस सप्ताह मॉनसून की चाल पर होगी निवेशकों की नजर

मुंबई(आरएनएस)। शेयर बाजारों में अगले सप्ताह उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहने की उम्मीद है. इस सप्ताह बाजार की चाल मॉनसून का रुख, घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक आंकड़े, वैश्विक बाजारों का रुझान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ पी आई) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) का रुख, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतें मिलकर तय करेंगे. मॉनसून के बारे में भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दीर्घकालिक औसत के हिसाब से इस साल 96 फीसदी तक बारिश होगी. इस दौरान शेयर बाजार में कई सरकारी कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं. सेंट्रल डिपॉजिटली सर्विसेज (इंडिया) (सी डी एस एल) 3.51 करोड़ शेयरों का आईपीओ जारी कर रही, जिसकी कीमत 145 से 149 रुपये प्रति शेयर रखी गई है. यह आईपीओ सोमवार को खुलेगा और बुधवार को बंद होगा. एरिस लाइफसाइंसेज मंगलवार को 2.88 करोड़ शेयरों का आई पी ओ लेकर आएगी, जिसकी कीमत 600 रुपये से 603 रुपये प्रति शेयर रखी गई है. यह आईपीओ शुक्रवार को खुलेगा. जीटीपीएल ने 1.8 करोड़ शेयरों के जरिए 300 करोड़ रुपये का वित्त जुटाया, जिसकी कीमत 167 से 170 रुपये प्रति शेयर रखी गई है. वैश्विक मोर्चे पर, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ई सी ब) की प्रसाशनिक परिषद की गैर-वित्तीय नीतिगत बैठक फ्रैंकफुर्ट में बुधवार को होगी. निक्केई फ्लैश जापान मैनुफैक्चरिंग इंडेक्स (पी एम आई), आई एच एस मार्किट फ्लैश फ्रांस कंपोजिट पी एम आई, आई एच एस मार्किट फ्लैश जर्मनी कंपोजिट पी एम आई, आई एच एस मार्किट फ्लैश यूरोजोन कंपोजिट पी एम आई आंकड़े शुक्रवार को जारी होंगे, जिनमें इन देशों के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के जून के आंकड़ों का ब्यौरा सामने आएगा.

चार साल में 4000 अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत

नई दिल्ली(आरएनएस)। सरकार के चार साल में डिजिटल अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचाने के लक्ष्य के बीच तकनीकी कंपनियों ने कहा कि इस अवधि में देश के पास डिजिटल अर्थव्यवस्था को 4000 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचाने की संभावना है. केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बात यहां डिजिटल अथवस्था से जुड़े उद्योग जगत की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों से बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रसाद ने कहा कि सरकार नयी इलैक्टॉनिक नीति, सॉफ्टवेयर नीति समेत कई नयी रणनीतियों को आगे बढ़ाएगी जो इस क्षेत्र को समर्थन प्रदान करेंगी. साथ ही डेटा की सुरक्षा के लिए भी एक ढांचा तैयार किया जाएगा.